Quebec, Lucien Bouchard, who was in the forefront of the sovereigntist campaign, has stated that Mr. Parizeau's statement does not reflect what the sovereigntists think or the way they behave.

नॉन-ओ॰वाई॰टी॰ "टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन

310. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में "जनपथ" एक्सचेंज के "नॉन-ओ॰वाई॰टी॰ श्रेणी के प्रतीक्षारत सभी आवेदकों को अप्रैल, 1996 तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध हो सकेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां, जनपथ एक्सचेंज, नई दिल्ली में नॉन ओ॰वाई॰टी॰ श्रेणी के प्रतीक्षारत सभी आवेदकों को अप्रैल, 1996 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी प्रयास किए जाएंगे।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

पंजाब में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

311. **श्री इकबाल सिंह:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान, राज्य में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने हैं;

(ग) इन उद्योगों में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰पी॰ सिंह देव): (क) से (घ) उदारीकरण के बाद से लेकर अक्तूबर, 1995 तक पंजाब राज्य के लिए लगभग 0.71 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 3242 करोड़ रु॰ के निवेश वाले 280 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त, पंजाब राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 515 करोड़ रु॰ के निवेश वाले और लगभग 0.28 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 100% निर्यातोन्मुखी/संयुक्त उद्यम/औद्योगिक लाइसेंस यूनिटों के लिए 17 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 426 करोड़ रु॰ के निवेश वाले और लगभग 0.37 लाख लोगों को रोजगार देने वाली 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अब तक पंजाब राज्य में कार्यान्वित की जा चुकी है। सामान्यतः परियोजना के कार्यान्वयन में 2-3 साल लगते हैं।

Border Dispute Between Maharashtra and Karnataka

312. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Maharashtra had met the Prime Minister and Home Minister in regard to Maharashtra Karnataka Border dispute; and

(b) the steps taken by Government to solve the border dispute?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS: (PROF. MEIJINLUNG KAMSON): (a) and (b) The boundary dispute between Maharashtra and Karnataka has been pending eversince the reorganisation of States in 1956. The Government of India has appointed the Mahajan Commission to look into this issue and it gave its recommendations in 1967 which were accepted by Karnataka in toto whereas the Government of Maharashtra rejected them. The differences are persisting.

The Government of India is of the view that the dispute has to be resolved primarily by the two State Governments concerned through discussions and mutual accommodation and it would be glad to render necessary assistance to the State Governments concerned in this regard.